दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 ▸ अंक : 7 ▸ गाजियाबाद, जुलाई, 2020 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 04 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

BSNL Connecting India

बीएसएनएल ने भी दिया चीन को झटका, 4जी टेंडर किया रद्द... P-4

कोरोना लाइव

605,220	359,896	17,848	10,810,307
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

अनलॉक-2 : यूपी सरकार ने नोएडा व गाजियाबाद के लिए बनाए अलग नियम

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

गाजियाबाद/नोएडा। अनलॉक–2 को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिले के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। यहां के जिलाधिकारियों को छूट दी गई है कि वह आवागमन के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस गाइडलाइन में भी दिल्ली बॉर्डर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने यह गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें रात्रि कर्फ्यूके संबंध मे कहा गया है कि मेरठ मंडल को छोड़कर प्रदेश में सभी जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यूरहेगा। जबकि मेरठ मंडल के जिलों में 10 जुलाई तक यह कर्फ्यूरात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। रात्रि कर्फ्यूमें औद्योगिक इकाइयों में मल्टीपल शिफ्ट में काम करने वाले, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों को छूट दी गई है।

इसके अलावा सभी राज्यों की सीमाओं से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन एनसीआर में स्थित

गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जनपदीय अधिकारियों से विचार–विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जिससे स्पष्ट है कि दिल्ली बॉर्डर पर अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योकि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली की वजह से जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और यदि वह बॉर्डर पर छूट देते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

उद्योगों को मिलेगा लाभ, रात्रि शिफ्ट में भी होगा काम

अनलॉक 2 में उद्योगों में रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात में आने–जाने की छूट दी गई है। जिससे वह रात्रि कर्फ्यूके दौरान भी आ जा सकेंगे। इसके बाद अब यहां की औद्योगिक इकाइयों में अब रात्रि में भी काम हो सकेगा। जिसकी मांग वह लंबे समय से कर रहे थे।

कंडक्टर से सीधे टिकट लेने के दिन होंगे हवा, कॉन्टेक्ट लेस टिकट का होगा ट्रायल

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जल्द ही सीधे कंडक्टर से टिकट लेने के दिन हवा हो जाएंगे। डीटीसी और कलस्टर बसों में श्कॉन्टेक्ट लेसश टिकट खरीदने की शुरुआत होने जा रही है। एक मार्ग पर गुरुवार को इसका ट्रायल भी किया जाएगा। कोरा. ना काल में सफर सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

क्यूआर कोड के जरिये लोग बगैर कंडक्टर के संपर्क में आए टिकट ले सकेंगे। एक साल से इस परियोजना को लेकर काम चल रहा था, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे जल्दी लागू किया जाएगा। मेट्रो नहीं चलने के कारण डीटीसी बसें सार्वजनिक परिवहन का बड़ा साधन हैं।

इस मार्ग पर ट्रायल : निजामुद्दीन से उत्तम नगर मार्ग पर इस योजना का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद इसे अन्य रूटों पर भी लागू किया जाएगा।

ई–गेट पास शुरू : दिल्ली हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर ई–गेट पास की सुविधा शुरू हो गई। इससे कार्गो में आया सामान ले जाते हुए लोगों को गेट पास के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। एजेंट को ऑनलाइन बिल व अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने

के बाद एक क्यू आर कोड प्राप्त होगा। वहीं, आवेदन के बाद आवेदनकर्ता की जानकारी अपने आप गेट पर तैनात कर्मचारी के पास चली जाएगी। बाहर जाते हुए केवल क्यूआर कोड स्कैन करवाना होगा।

पहले बिल जमा करने और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एजेंटों को काउंटर पर गेट पास के लिए आवेदन करना पड़ता था। भीड़ होने से घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब ई–पास लेने की व्यवस्था सुगम होगी। इससे फर्जीवाड़ा कर सामान कार्गो से बाहर निकालने जैसे मामले भी रुकेंगे।

कोरोना से डॉक्टर की मौत, अस्पताल ने परिवार को थमाया 14 लाख का बिल

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

नोएडा। नोएडा के एक निजी कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के नाम पर मनमानी रकम वसूलने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने 20 दिन इलाज करने के बदले उन्हें करीब 14 लाख रुपये का बिल थमा दिया है।

नोएडा के सेक्टर 11 में रहने वाले एक डॉक्टर निजी क्लीनिक चलाते थे। डॉक्टर की तबीयत खराब होने पर 7 जून को सेक्टर–62 स्थित निजी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी कोरोना संक्रमण की जांच कराई गई। 8 जून को उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 13 जून को उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। वह करीब 15 दिन वेंटिलेटर पर रहे और रविवार को उनकी मौत हो गई। वह बीयूएमएस डॉक्टर थे और सेक्टर–11 में क्लीनिक चलाते थे और गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहते थे। उनके बेटे ने बताया कि आईसीएमआर के तय रेट के अनुसार गंभीर रोगी के इलाज में प्रतिदिन 10 हजार रुपये खर्च आता है।

वेंटिलेटर व पीपीई किट का चार्ज 10 हजार अधिक मानकर प्रतिदिन का खर्च 20 हजार रुपये भी लगाएं तो भी 20 दिन के इलाज का खर्च 4 लाख रुपये आता है, लेकिन अस्पताल ने इलाज के बदले 13.77 लाख रुपये मांगे हैं।

उधर, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज से संबंधित ब्योरा लिया जा रहा है। प्रत्येक जांच और दवा का रिकॉर्ड हमारे पास है। मरीज को दो बार 40–40 हजार के इंजेक्शन भी दिए गए थे। मृतक का शव देने के लिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है।

नोएडा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 31 जुलाई तक बढ़ाई गई धारा-144

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

नोएडा। पूरे देश में एक जुलाई से अनलॉक 2.0 शुरू हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोविड–19 के मामलों को देखते हुए यहां 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक अनलॉक–2 घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर जनपद गौतम बुद्ध नगर में पहले से जारी धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अपर उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग, संस्थान इत्यादि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई रात्रि तक रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति/वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गति. विधियों को छोड़कर)।

उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। शिवाय ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वास्थ संबंधी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क/फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित है। अधिकारी ने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर, अन्य किसी भी व्यक्ति का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला चिकित्सालय में टाटा समूह द्वारा तैयार किए जा रहे 400 बेड के कोविड अस्पताल का आज जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निरीक्षण किया। सुहास एल वाई ने बताया कि जनपद में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस अस्पताल को जल्द तैयार करने का आदेश दिया गया है, ताकि संबंधित अस्पताल में तेजी से कार्य पूर्ण करते हुए कोविड अस्पताल के रूप में इसका संचालन किया जा सके।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम–जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2020

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING				DELHI MINIMUM WAGES	PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	1/3/2019	1/7/2019	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	8776.83	9024.24	5850.00	8278.40 8070.40	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	9556.83	*	6162.00	8486.40 8278.40	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	9475.43	*	* *	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	9949.19	*	* *	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	10453.83	*	6474.00	8720.40 8486.40	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	10446.65	*	* *	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	10969	*	* *	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	11485.83	11517.45	7774.00	* *	*

अनामिका शुक्ला केस रू 50 करोड़ से ज्यादा की सैलरी ले चुके 117 फर्जी टीचरों को लौटाना होगा पूरा वेतन

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

नई दिल्ली। अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर केस के खुलासे के बाद यूपी में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। फर्जी कागज तैयार करा कर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक–शिक्षिकाओं पर शासन शिकंजा कस दिया है। एटा के 117 शिक्षकों से रिकवरी का आदेश शासन ने बीएसए को दिया है। यह 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। शासन ने निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार नरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन से जिले के 117 फर्जी शिक्षक–शिक्षिकाओं से वेतनादि की रिकवरी का आदेश मिला है। शिक्षकों से रिकवरी का आगणन पूर्ण होने पर उनको नोटिस जारी किया जाएगा। फर्जी शिक्षक–शिक्षिकाओं को दो बार नोटिस जारी किया जाएगा। पैसा जमा होने पर उसके बाद आरसी जारी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर

से ही पूर्ण होनी हैं। आगणन, नोटिस प्रक्रिया में दो–तीन दिन का समय लगेगा। नोटिस में फर्जियों को निर्धारित समय धनराशि जमा करने को भी कहा जाएगा। शासन के इस नए फरमान ने फर्जी शिक्षक–शिक्षिकाओं की नींद उड़ा दी है। अभी तक फर्जी शिक्षक–शिक्षिकाएं कोर्ट का सहारा लेकर बचते रहे हैं। डा. भीमराव अंबेडकर विश्व विद्यालय के फर्जी एवं टैम्पर्ड अभिलेख पर प्रदेशभर में नौकरी कर रहे 2823 शिक्षक–शिक्षिकाए शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। विश्व. विद्यालय ने इनकी एसआईटी जांच कराई थी। एसआईटी जांच में जनपद के 122 फर्जी शिक्षक–शिक्षिकाएं शामिल थे। उसमें से पांच शिक्षक–शिक्षिकाओं से रिकवरी के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। शासन ने इनके नाम की सूचनी 20 मई को जारी की थी। उसके बाद 117 फर्जियों से रिकवरी आदेश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। संजय सिंह, बीएसए एटा ने बताया कि फर्जी शिक्षिकों से रिवकरी के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी जारी की जाएगी।

शासन की प्रथम सूची में यह पांच थे शामिल

20 मई को शासन से जारी हुई फर्जी शिक्षकों से रिकवरी सूची में एटा के पांच शिक्षकों के नाम शामिल थे। उनमें ब्लॉक शीतलपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नगला सुम्मेर के प्रधानाध्यापक प्रियंका, ब्लॉक सकीट क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चपरई के प्रधानाध्यापक गीता, प्राथमिक विद्यालय रजकोट सहायक अध्यापक आभा, ब्लॉक जलेसर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय किसर्रा अमृतपुर की सहायक अध्यापक अनीता, ब्लॉक अलीगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक वृंदावन बाथम शामिल हैं। इन पांच से लगभग दो करोड़ की रिकवरी का आगणन तैयार किया गया है। वही 117 शिक्षकों से 50 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो सकती है।

भारत के बाद अमेरिका से भी लग सकता है चीन को झटका, उठी टिकटॉक बैन करने की मांग

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

नई दिल्ली। हाल ही में एलएसी पर चीन का बदमाशियों को देखते हुए भारत ने ड्रैगन के डिजिटल मार्केट पर वार किया और एक ही झटके में टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप पर पूरी तरह देश में बैन कर दिया। उधर कोरोना से त्रस्त अमे. रिका भी चीन से कम ऊबा हुआ नहीं है। चीन के खिलाफ रोज नए नए बयान दे रहे अमेरिका में भी अब टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ रही है। दरअसल भारत की तर्ज पर कुछ अमेरिकी सांसद इस बैन की मांग उठा रहे हैं। सांसदों ने अमेरिकी सरकार से कहा कि छोटे छोट वीडियो शेयर करने वाले ये ऐप देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। गौरतलब है कि सोमवार को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसे चीन के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। सरकार ने इस फैसले से जहां चीन को सख्त संदेश दिया है वहीं भारत में मोटा मुनाफा कमाते हुए यूजर्स डेटा से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। टिकटॉक जैसी ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, जिसके सहारे बाइट

डांस जैसी कंपनियां फेसबुक जैसी कंपनियों को टक्कर देने का सपना देख रही थी। कुछ ही सालों में टिकटॉक ने भारत पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी। करोड़ों मोबाइल में ऐप डाउनलोड से टिकटॉक खूब कमाई भी करने लगा था। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज तीन महीनों में इस ऐप से कंपनी को 25 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था। ऐप पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा था।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

Editorial

03 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2020

सम्पादकीय

चुनौती का सामना

सत्येन्द्र सिंह

महामारी से उपजे संकट के दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इससे बचाव के लिए अपनाए गए जरूरी उपायों की वजह से गरीब तबकों के लोगों के सामने जिस तरह जिंदा रह पाने लायक भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है, उसमें सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह इस समस्या का कोई ठोस हल निकाले। मार्च महीने में जब पूर्णबंदी लागू की गई, तभी से सबसे बड़ी चिंता यही सामने थी कि जिन लोगों के खाने-पीने की निर्भरता ही रोजाना की मजदूरी या दिहाड़ी पर टिकी थी, वे कैसे खुद को बचाएंगे। इस समस्या का दायरा शहरों-महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अब भी बना हुआ है। रोजी-रोटी या रोजगार के अभाव में ऐसे तमाम लोग हैं, जो किसी मदद के बूते अपना वक्त काट रहे हैं। हालांकि अप्रैल महीने से सरकार ने मुफ्त अनाज मुहैया कराने की व्यवस्था की और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तात्कालिक राहत मिली। लेकिन अब खुलने की ओर बढ़ चली पूर्णबंदी का दौर जैसे-जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, उसमें अभाव से जूझ रहे लोगों के सामने संकट गहराता जा रहा है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में एक बड़ी घोषणा यह की कि मुफ्त अनाज वितरण की योजना अब अगले पांच महीने यानी नवंबर तक और जारी रहेगी। इसके तहत करीब अस्सी करोड़ लोगों को पांच किलो गेहूं या चावल और साथ में एक किलो चना दिया जाएगा, ताकि कोई रोजगार या मजदूरी का काम नहीं मिलने की स्थिति में उनके सामने भूखे रहने की नौबत नहीं आए। इस घोषणा से यह संकेत भी उभर रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से लागू पूर्णबंदी अब देश के अलग-अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से खुलने की ओर जरूर बढ़ रही है, लेकिन उसके असर की वजह से रोजी-रोजगार की स्थिति में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं आने जा रहा है। अगर यह हालत बनी रहती है तो सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के सामने होगी, जो पहले ही काम-धंधे पूरी तरह ठप होने के चलते आर्थिक रूप से पूरी तरह लाचार हो चुके हैं और उनके पास अपना और अपने परिवार का पेट भरने तक के लिए पैसे या अनाज नहीं हैं। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद देश की दो-तिहाई आबादी को दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलो अनाज हर माह देने की व्यवस्था की गई थी। अब मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की योजना कुछ समय के लिए जारी रखती है तो निश्चित रूप से यह अभाव से लड़ते लोगों की एक अतिरिक्त और बड़ी मदद होगी।

मगर चावल या गेहूं के सहारे पोषण और सेहत की तस्वीर क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अगर इसके साथ दालें और खाने-पीने की दूसरी जरूरी चीजें भी दी जातीं तो बेहतर होता। इसके अलावा, यह भी देखने की जरूरत है कि मुफ्त अनाज की योजना और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज की सुविधा के दायरे से अगर राशन कार्ड या जरूरी दस्तावेजों के अभाव की वजह से प्रवासी मजदूर या कुछ दूसरे लोग छूट रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें भी मदद पहुंचाई जाए। हर साल काफी मात्रा में अनाज के सड़ कर बर्बाद हो जाने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि जब तक देश भर में काम-धंधे या रोजगार पूरी तरह ठप हैं, तब तक लोगों के सामने भूखे रहने की नौबत न आए।

हालात यही रहे तो पेट्रोल-डीजल के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा

हैलो नमस्कार जी, क्या यह पेट्रोल–डीजल बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर शाखा है? अभिनव ने बड़ी सौम्यता के साथ अपने एरिया के लोकल बैंक को फोन लगाया। दूसरे छोर से बैंक कर्मचारी ने उत्तर देते हुए कहा– जी हाँ। बताइए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? अभिनव ने पूछा– क्या आप मेरी बात प्रबंधक जी से करवा सकते हैं? बैंक कर्मचारी बड़ी विनम्रता के साथ बोला– सर जी क्षमा चाहता हूँ। आज प्रबंधक जी से बात नहीं हो सकती। ऑडिट का काम चल रहा है, वे बड़े व्यस्त हैं। वैसे आप प्रबंधक जी से क्या बात करना चाहते हैं? इस पर अभिनव ने अपनी दुविधा बताते हुए कहा– दरअसल बात यह थी कि मैंने हाल ही में एक कार खरीदी है। मेरी शनी कहिए या मेरी साढ़े साती कि उसके अगले दिन से पेट्रोल–डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। अब क्या बताऊँ कार निकालना दुश्वार हो गया है। घर पर पड़ी–पड़ी सड़ रही है। ऊपर से घरवालों की झिक–झिक अलग। कार है कि बिना डीजल पिये एक इंच हिलने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए मैं अपनी कार के लिए डीजल लोन लेना चाहता हूँ। इसका प्रॉसेस क्या होता है, यही सब पता लगाने के लिए प्रबंधक जी से बात करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर बैंक कर्मचारी थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहने लगा– बस इतनी–सी बात के लिए आप प्रबंधक जी से बात करना चाहते हैं? वह तो मैं ही बता सकता हूँ। कोरा. ना का समय चल रहा है इसलिए बैंक सीमित समय के लिए काम कर रहे हैं। जब तक आप बैंक आयेंगे, फॉर्म भरेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ लोन लेने के लिए मारा–मारी चल रही है। आप एक काम कीजिए। हमारी वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट पी डी बी आई ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन से फार्म डाउनलोड कर लीजिए। उसे भर लीजिए। उसके साथ तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ और सरकारी नौकरी करने वाले गारंटर को साथ ले आइए। यह सब काम आप जितना जल्द करेंगे आपको उतना लाभ होगा। देर करेंगे तो लोन के बारे में भूल जाइए। अभिनव ने बैंक कर्मचारी को धन्यवाद कह फोन काट दिया। थोड़ी देर पहले फुले हुए गुब्बारे की तरह दिखने वाला अभिनव हवा निकलते ही सिकुड़े हुए गुब्बारे–सा दिखने लगा। लोन का प्रॉसेस सुन उसका सिर चकरा गया। पत्नी ने अभिनव को समझाते हुए कहा– कोई बात नहीं जी। मेरी एक सहेली है। उसका पति गांधीनगर शाखा के प्रबंधक को अच्छी तरह से

जानता–पहचानता है। दोनों में खूब जमती है। मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है। उसने मुझे बताया कि लोन का काम हो जाएगा। सिर्फ आप बैंक का जो प्रॉसेस है उसे पूरा कर लीजिए। यह सब सुन अभिनव सुपरमैन की तरह हवा में उड़ने लगा। उसने फटाफट बैंक का प्रॉसेस पूरा किया। अगले दिन सुबह–सुबह बैंक खुलते ही जाकर अभिनव ने आसन जमाया। उसके साथ उसकी पत्नी, पत्नी की सहेली, सहेली का पति, गारंटर सभी थे। वैसे प्रबंधक जी उस दिन भी व्यस्त थे। लेकिन पहले से ही फिल्डिंग जमाकर रखने का लाभ यह हुआ कि अभिनव को कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी लोग प्रबधंक जी के कमरे में ऐसे बैठे थे मानो जैसे खुद के घर में बैठे हों। ऊपर से चाय–पानी का मजा अलग से। लोन की बात शुरु हुई। प्रबंधक ने अभिनव को समझाते हुए कहा– आप निश्चिंत रहिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपके लोन प्रॉसेस में एक समस्या है। आपका लोन एमाउंट बहुत कम है। छोटे–छोटे लोन में झिक–झिक अधिक होती है। लोन कब तक पास होगा कुछ कह नहीं सकते। मुझसे जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हीं के हाथों में सब कुछ होता है। तब तक आपको साइकिल चलाकर गुजारा करना होगा। अगर मंजूर है तो कहिए लोन प्रॉसेस अभी शुरु कर देता हूँ। हाँ, यदि आप लोन जल्दी चाहते हैं तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। आप यह लोन निजी तौर पर न लेकर अपनी कंपनी की ओर से लें। और लोन अमाउंट में शून्यों की संख्या बढ़ा दें। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ऐसे लोन जल्दी पास कर दिए जाते हैं। बड़े लोनों में बड़े बाबुओं की बड़ी दिलचस्पी होती है। तब आप एक कार क्या अपनी कंपनी की सभी कार और अन्य गाड़ियाँ भी दौड़ा सकते हैं। खुदा न खास्ता मान लीजिए कल के दिन कुछ ऊँच–नीच हो गई तो अपने परिवार के साथ निकल जाइए फॉरेन ट्रिप पर।

कहीं खो न जाए आपके पैरों की सुंदरता, रखें इस तरह से ख्याल

जिस तरह से आप अपने चेहरे और बालों समेत हाथों का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह अपने पैरों की भी देखभाल करनी चाहिए। ज्यादातर महिलाएं अपने पैरों पर ध्यान नहीं देती, उनके अनुसार पैर लोगों की नजरों से छिपे हुए हैं। हालांकि पैरों का ख्याल रखना सिर्फ सुंदरता बढ़ाना नहीं है। इसकी देखभाल सेहत और फिटनेस के तौर पर भी जरुरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैर हमारे पूरे शरीर का बोझा उठाते हैं और इनका ध्यान रखने की अधिक जरुरत है। वहीं, आज हम आपको त्वचा विशेषज्ञों द्वारा बताए गए कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने पैरों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन टिप्स के जरिए आप अपने पैरों को काफी सुंदर और आकर्षित भी बना सकते हैं। आइए आपको उन शानदार टिप्स के बारे में बताते हैं.

पैर बनेंगे मुलायम : त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार दिनभर जूते–चप्पल पहनने से पैरों की त्वचा पर खासा असर पड़ता है। चलना, उठना, बैठना, खड़े होना या फिर भागदौड़ करना इन सभी में पैरों का इस्तेमाल होता है। ये रोजाना अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इनकी देखभाल करना जरुरी है। त्वचा विशेषज्ञों की मानें तो कहीं भी बाहर से आने पर सबसे पहले अपने पैरों को पानी से धोकर सुखा लेना चाहिए। इसके सुखने के बाद उन पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी जरुर लगाएं। मॉइस्चराइज करने के लिए आप नारियल या जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से रोजाना करने पर पैरों की त्वचा मुलायम बनी रहेंगी। अगर रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में 3 बार जरुर करें।

तलवों की दरारें होंगी दूर : ज्यादातर लोगों के पैरों के तलवों पर दरारें पड़ जाती है। इसके लिए बाजार में कई महंगी–महंगी क्रीम भी मौजूद है। हालांकि आप इसे घरेलू तरीके से भी सही कर सकते हैं। त्वचा विशेषज्ञों के मुता. बिक अगर आप अपने पैरों को दस मिनट के लिए गर्म पानी में नमक डालकर भोगोएंगे तो

10 मिनट के बाद आपके पैर थकान रहित और ताजगी महसूस करेंगे। अगर पैरों में गहरी दरारें हैं तो पानी से निकाले के बाद पत्थर के बने झांवे से उसे रगड़ें और साफ कर लें। इससे आपके तलवों में पड़े स्पॉट खत्म हो जाएंगे।

ऐसे बनाएं पैरों को सुंदर और मुलायम : त्वचा विशेषज्ञों की मानें तो आप अपने पैरों की देखभाल रसोई में मौजूद चीजों से भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पैर खुरदरे हैं और एड़ियां फटी हुई है वो बेसन का इस्तेमाल कर इस समस्या को सही कर सकते हैं। इसके लिए बेसन में नींबू के रस की कुछ बूंदे, थोड़ी सी मलाई और 1 चुटकी हल्दी को ठीक तरह से पहले मिक्स करें। इसके बाद इस मिश्रण को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इस मिश्रण को अपने पैरों के तलवों पर 15 मिनट के लिए लगा लें। इसके बाद गरम पानी से अपने पैरों को अच्छे से धोएं और धीरे–धीरे स्पंज करें। इस तरह से अगर आप हफ्ते में 1 बार करेंगे तो आपके पैर सुंदर और मुलायम बने रहेंगे।

टैल्कम पाउडर से होगा फायदा : अक्सर ऊंची एड़ी या बंद जूते से पैरों में काफी तकलीफ हो जाती है। कई बार तो नए जूतों से पैर कटने भी लगता है। ऐसे में जरुरी है कि आप आरामदायक जूते–चप्पलों का ही प्रयोग करें। वहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और बंद जूता पहनना आपके लिए जरुरी भी है तो इससे होने वाले नुकसानों से बचने के लिए अपने पैरों में टैल्कम पाउडर लगाएं। इसकी मदद से आपके पैर सुखे रहेंगे और गर्मियों में ये काफी फायदेमंद रहेगा।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

- EVENTS MANAGEMENT
- PR MANAGEMENT
- ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2020

600 लाभार्थियों दी गई टूल किट: जिलाधिकारी

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत जिलें में 1035 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर 600 लाभार्थियों को टूल किट प्रदान की गई। इस दौरान एक जनपद एक उत्पाद योजना के कुल 18 लाभार्थियों को 3 करोड 48 लाख रुपए का लोन दिया गया, इतना ही नहीं जनपद में अब तक 4711 इकाईयों को कुल 311 करोड रुपए का लोन दिया गया। डीएम अजय शंकर पांडये ने बताया कि जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के लाभार्थियों को लेकर ऑनलाईन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिसके तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित की गई, योजना के तहत 18 लाभार्थियों को धनराशि 3.48 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। इस अवसर पर कोविड–19 के दौरान बैंकों द्वारा एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने वाले ऋण की घोषणा भी की गई, जिसके तहत 4711 इकाइयों को 311 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

उक्त कार्यक्रम में ऑनलाईन प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल उपस्थित रहे।

फर्म की बढी मुश्किलें, अब दो माह से ज्यादा नहीं बढ पाएंगी मियाद

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

गाजियाबाद। भोपाल की उस फर्म पर संकट खडा हो गया है, जिसके द्वारा जैम पोर्टल के आधार पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए से कम्प्यूटर आपरेटर कांटेक्ट पर उपलब्ध कराने का ठेका ले लिया। जैम पोर्टल के माध्यम से आपरेटर आदि कांटेक्ट पर रखने के लिए तय की गई फर्मों का अनुबंध केवल दो माह ही बढाया जा सकेगा। प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने एक आदेश के माध्यम से प्रदेश के तमाम अधीनस्थ आला अधिकारियों को उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के निर्णय की तरफ ध्यान दिलाया है। श्री सिंघल ने जारी किए आदेश में उल्लेख किया गया कि अभी तक शासन के द्वारा अनुबंध के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर आदि रखने का निर्धारण जैम पोर्टल के माध्यम से किए जाने के आदेश दिए गए है। शासन के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम सेवायोजना विभाग में कार्रवाई की स्थिति को देखते हुए 18 दिसंबर 2019 में उल्लिखित अनुबंध की वैधता अवधि दो माह बढा दी जाए। इस अवधि में अपेक्षित कार्रवाई को सूक्ष्म,लघू एवं मध्यम उदयम तथा सेवायोजन विभाग प्रत्येक दिशा में पूर्ण करा ले। उच्च न्यायालय की पीठ का निर्णय प्रभावी रहेगा। बताते है कि जिस वक्त जीडीए के द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटर आपरेटर रखने की दिशा में भोपाल की फर्म के साथ अनुबंध किया।

आरटीओ और पुलिस पर भारी डग्गेमार बसे का संचालन

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

गाजियाबाद। कहावत है कि यदि आपके चांदी के जूते में ताकत है तो उसके रहते कुछ भी कराया जा सकता है। जहां एक तरफ तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोरोना थामें नहीं थम रहा है। वहीं किसी को देश की राजधानी दिल्ली सीमा से लगे गाजियाबाद की सडकों पर दौड रही डग्गेमार बसें दिखाई नहीं दे रही है। इन डग्गेमार बसों के माध्यम से कोरोना के विस्तार को बढावा दिया जा रहा है, वहीं ये बसें यूपी रोडवेज की आय पर भी भारी पड रही है। रोडवेज के कर्मचारी नेताओं की मानें तो चूंकि थाना पुलिस और आरटीओ को हिस्सा पहुंचता है तो ऐसे में किसी को भी ये बसें दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो इन डग्गेमार बसों के संच. ालन पर प्रतिबंध आवश्यक है। रोडवेज के कर्मचारी नेताओं में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि यूपी रोडवेज अपनी तमाम बसों का संचालन कौशांबी

बस अडडे से कर रहा है, जबकि इन डग्गेमार बसों का संचालन कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली की सडकों से हो रहा है। यहां बता दे कि दिल्ली में सख्ती के बीच तो ये तमाम डग्गेमार बसें जीडीए के द्वारा विकसित कौशांबी कालोनी की सडकों पर आ गई थीं।

बताते है कि दिल्ली पुलिस की छूट मिलते ही एक बार फिर से ये बसें फिर दिल्ली की सडकों से दौड रही है। बताते है कि इन बसों को सेनेटाइज करने की भी व्यवस्था नहीं की गई है और जो मुसाफिर इन बसों में सफर करते है, उनके टैस्ट की भी दूर तक व्यवस्था नहीं है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला शाखा के अध्यक्ष गुलजार अहमद ने कहा कि परिषद के अभी तक ये समझ से दूर है कि आखिर किन प्रभावशाली प्रदेश सरकार के नेताओं की ये डग्गेमार बसें है जिस पर हाथ डालते हुए आरटीओ और पुलिस विभाग के अफसरों के हाथ कांपते है। अथवा कितनी मोटी रकम वसूल की जाती है जो कि इन डग्गेमार बसों पर एक्शन नहीं हो पा रहा है।

सेनेटाइजेशन के नाम पर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है जीडीए

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

गाजियाबाद। कोरोना काबू में आते हुए नहीं दिख रहा है। तमाम दावों के बावजूद हर रोज नए मामले सामने आ रहे है। जिले में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद देखा जाए तो कोरोना से प्रभावित इलाकों में सेनेटाइजेशन के नाम पर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। अभी तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए उन तमाम कालोनियों में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहा जो कि जीडीए के देखरेख में है। जीडीए के अधिकारियों के द्वारा तर्क दिए जा रहे है कि चूंकि तमाम कालोनियों से निगम हाउस टैक्स वसूल रहा है, ऐसे में निगम को चाहिए कि वह सभी कालोनियों में नियमित तौर से सेनेटाइजेशन करें। जीडीए के अधिकारियों ने ये भी खुलासा किया कि क्रासिंग एवं राजनगर एक्सटेंशन आदि में देखा जाए तो तमाम आग्रह के बाद पिछले तीन माह के दौरान केवल तीन बार ही सेनेटाइजेशन के लिए गाडी भेजी, जो कि मुख्य मार्गों से औपचारिकता करके लौट गई। ये भी खुलासा हुआ कि जीडीए के द्वारा इस बीच संसाधन की उपलब्धत सुनिश्चित नहीं की गई है। प्रवर्तन विभाग अब बिल्डर एवं आरडब्लूए पर सेनेटाइजेशन के लिए दबाव बना रहे है। जो कुछ सोसाइटियों में आरडब्लूए के द्वारा सेनेटाइजेशन किया जाता है, वहीं फोटो कराते हुए वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है। बताते हैं कि क्रासिंग की जिस ग्लोबल सोसाइटी को तीन दिन पहले सील किया गया,उसमें अभी तक सेनेटाइजेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। जीडीए बोर्ड सदस्य एवं निगम पार्षद हिमांशु मित्तल एवं हाजी आसिफ ने कहा कि ये बडा ही दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से आमना सामना न हो इसके लिए जीडीए में जनप्रतिनिधियों की एंट्री बेन की गई है और जीडीए की हेल्प लाइन भी बेकार पडी है। यहां बता दे कि पिछले एक माह से देश की राजधानी दिल्ली से लगे गाजियाबाद के हालात दिनों दिन बदतर हो रहे है। जबकि मधुबन बापूधाम, इंदिरापुरम, तुलसी निकेतन, राजनगर एक्सटेंशन, क्रासिंग सिटी आदि की देखरेख अभी भी जीडीए के पास है। इस बीच ये साफ हो गया है कि फिलहाल कोरोना पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। बताते है कि जीडीए अभी तक अपनी देखरेख वाली कालोनियों में नियमित तौर से सेनेटाइजेशन के लिए संसाधन भी नहीं जुटा पाया है। इसी का नतीजा ये है कि जीडीए के देखरेख वाली कालो. नियों में लगातार कोरोना के केश बढ रहे है। इंदिरापुरम में कोरोना के चलते कई लोगों की मौतें तक हो चुकी है।

59 चीनी एप बंद होने के बाद बीएसएनएल ने भी दिया चीन को झटका, 4जी टेंडर किया रद्द

–उद्योग विहार (जुलाई 2020)–

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने 4जी दूरसंचार नेटवर्क उन्नत बनाने को लेकर जारी करोड़ों रुपये की निविदा रद्द कर दी। सरकार ने कंपनी को किसी भी चीनी उपकरण का उपयोग नहीं करने को कहा है, जिसके बाद निविदा रद्द की गयी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत–चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हाल में हिंसक झड़प के बाद चीनी वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है। भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने 4जी निविदा रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया। इस बारे में और जानकारी के लिए बीएसएनएल के चेयरमैन के साथ संपर्क नहीं हो सका। बीएसएनएन के नोटिस के अनुसार ''23 मार्च 2020 को जारी निविदा रद्द की जाती है....।'' यह निविदा 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियिरंग, आपूर्ति, उसे लगाने, परीक्षण, चालू करने और सालाना रखरखाव से जुड़ी थी। इस नेटवर्क को बीएसएनएल के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों तथा एमटीएनएल के दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्रों में पूरी तरह से मुकम्मल कर लगाया जाना था। इसमें कहा गया है कि उचित प्राधिकरण से मंजूरी के बाद निविदा

को रद्द किया गया है। सूत्रों ने जानकारी दी कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल से 4जी उन्नयन के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था। इस निर्देश के पालन करने का सीधा मतलब है कि कंपनी को नयी निविदा जारी करनी पड़ेगी। सूत्रों के अनुसार नई निविदा जारी की जाएगी जिसमें मेक इन इंडिया पर जोर होगा। उल्लेखनीय है कि करीब एक पखवाड़े पहले दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल से चीनी दूरसंचार उपकरणों का 4जी उन्नयन योजना में उपयोग करने से मना किया था।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह